

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]	दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2019/कार्तिक 22, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 289
No. 314]	DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2019/KARTIKA 22, 1941	[N.C.T.D. No. 289

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग
(स्थानीय निकाय निदेशालय)
अधिसूचना
दिल्ली, 13 नवम्बर, 2019

सं. एफ. 1(9)/एडीएलबी/ओएस-5/2015/000372362/14143-53.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल) नियम, 1993 के अधिक्रमण में, सिवाय उन मामलों के जिन्हें उक्त अधिक्रमण से पूर्व किया जाना था अथवा किया जाना छोड़ देना था, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद्वारा निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सेवा की शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल) नियम, 2019 बनाते हैं, अर्थात् :-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त कार्यालय के लिए सेवा की शर्तों और कार्यालय के कार्यकाल से संबंधित मामलों अथवा उनसे जुड़ने वाले आकस्मिक मामलों को निर्धारित करने के लिए नियम।

अध्याय—I

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ—(i) इन नियमों को निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सेवा की शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल) नियम, 2019 कहा जा सकता है।

(ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. व्याख्या—(1) इन नियमों में जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हों:-

क. 'अधिनियम' से अभिप्राय अद्यतन संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) से है।

- ख. 'प्रशासक' से अभिप्राय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है।
- ग. 'निर्वाचन आयुक्त' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 7 (1) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243के और 243जेडए के अंतर्गत नियुक्त निर्वाचन आयुक्त से है।
- घ. 'सरकार' से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से है।
- ड. 'न्यायाधीश' से अभिप्राय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से है।

अध्याय II

निर्वाचन आयुक्त का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें

3. प्रशासक द्वारा सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से किसी अधिकारी अथवा भारत सरकार (संघ शासित क्षेत्र कैंडर) की सेवा में सचिव पद से सेवानिवृत्त हो चुके अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सेवारत/सेवानिवृत्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को, वेतनमान के शीर्षस्थ स्तर में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त का वेतन, भत्ते तथा अन्य पूर्वनिर्धारित भुगतान और सेवा की अन्य शर्तें दिल्ली उच्च न्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश के समान होंगी जैसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) में शर्तें निहित हैं और इस विषय के संबंध में उनके तहत भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियम और अनुदेश तैयार किए जाते हैं।

बशर्ते यदि अपनी नियुक्ति के समय निर्वाचन आयुक्त किसी पूर्व सेवा से पेंशन (अशक्त तथा घायल व्यक्तियों को मिलने वाली पेंशन के अलावा) प्राप्त कर रहे हों, तो निर्वाचन आयुक्त के रूप में उन्हें मिलने वाला वेतन निम्नानुसार घटा दिया जाएगा—

(क) उस पेंशन राशि के बराबर राशि, और

(ख) यदि उन्हें, पहले ऐसी किसी नियुक्ति के लिए पिछली किसी सेवा की देय पेंशन के हिस्से के बदले राशि बकाया हो, तो पेंशन के उस हिस्से की कम्प्यूटिड वैल्यू।

बशर्ते साथ ही किसी भी स्थिति में निर्वाचन आयुक्त को मिलने वाला वेतन निर्वाचन आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्त से पूर्व सेवानिवृत्ति के समय मिल रहे वेतन से कम नहीं होगा।

बशर्ते साथ ही वे सेवा शर्तें, जिनके बारे में इन नियमों के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है, इस दौरान वैसे ही रहेंगे, जैसा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिए सरकार में वेतन स्तर निर्धारित होते हैं।

कार्यकाल

4. निर्वाचन आयुक्त अपने पद ग्रहण की तारीख से 06 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहेंगे।

बशर्ते उपरोक्त अवधि के समाप्त होने के बाद, राज्य के निर्वाचन आयुक्त तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता और उक्त उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं कर लेता किंतु यह अवधि किसी भी मामले में 06 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बशर्ते साथ ही निर्वाचन आयुक्त, किसी भी समय, प्रशासक को संबोधित अपने लिखित आवेदन द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं।

बशर्ते साथ ही निर्वाचन आयुक्त को सिवाय उस तरीके से उनके पद से हटाया नहीं जाएगा, जैसा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए आधार तय होते हैं।

5. (1) कोई व्यक्ति जिसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है, उन्हें इन नियमों के नियम 6 के उप-नियम (3) के अनुसार, यथाविनिर्धारित छुट्टियां प्रदान की जाएंगी।

(2) निर्वाचन आयुक्त को छुट्टी प्रदान करने अथवा अस्वीकृत करने तथा उन्हें प्रदान की गई छुट्टियां बहाल करने अथवा उनमें कटौती करने की शक्ति प्रशासक को विहित होगी।

6. (1) जब कोई निर्वाचन आयुक्त अपना पद त्याग देता है (जैसा नियम (4) में निर्दिष्ट है, उस तरीके से अथवा त्यागपत्र द्वारा), तो ऐसे पद त्याग की स्थिति में वह निम्नलिखित का पात्र होगा—

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय पेंशन के बराबर पेंशन।

(ख) ऐसी पेंशन में पेंशन का कम्प्यूटेशन, परिवार पेंशन और उपादान राशि शामिल होगी, जैसा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय होती है।

(2) सिवाय ऐसे मामलों के, जहां निर्वाचन आयुक्त त्यागपत्र देते हुए अपना पद त्याग देते हैं, तो इन नियमों के उद्देश्य से, यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपना पद त्याग दिया है और केवल तभी यह माना जाएगा कि —

(क) उन्होंने नियम 4 में विनिर्दिष्ट कार्यकाल को पूरा किया है, अथवा

(ख) उनकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, अथवा

- (ग) उन्हें उसी प्रकार अपने पद से हटाया गया है, जैसा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए आधार तय होते हैं।
- (3) निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति निम्नलिखित छुट्टी का पात्र होगा, अर्थात् –
- (i) सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर वर्ष के लिए तीस दिनों की अर्जित छुट्टी अथवा उस वर्ष के किसी भाग के दिनों का आनुपातिक संख्या के भाग के लिए अर्जित छुट्टी का पात्र होगा और अर्जित छुट्टी का छुट्टी वेतन उसके छुट्टी पर जाने से पूर्व प्राप्त वेतन के समान होगा।
 - (ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर वर्ष के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र अथवा निजी कार्यों के लिए बीस दिन की अर्द्ध वेतन छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी के लिये छुट्टी वेतन अर्जित छुट्टी के दौरान देय छुट्टी वेतन के आधे वेतन के बराबर देय होगा।
 - (iii) यदि अर्द्ध वेतन छुट्टी स्वयं की चिकित्सा के आधार पर ली जाती है तो उसके साथ सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर उक्त अवधि को पूर्ण वेतन छुट्टी में परिकलित किया जा सकता है।
 - (iv) बिना वेतन और भत्तों के अधिकतम एक सौ अस्सी दिन की असाधारण छुट्टी एक कार्यकाल में दी जा सकती है, हालांकि, यदि स्वयं की बीमारी के आधार पर ऐसी छुट्टी ली जाती है तो कार्यालय के कार्यकाल में कोई ब्रेक नहीं होगा।
- (4) आयोग में कार्यकाल की समाप्ति के बाद, निर्वाचन आयुक्त अपने छुट्टी खाते में बकाया अर्जित छुट्टी के बराबर नकद राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे बशर्ते उनके द्वारा इस उप-नियम के अन्तर्गत छुट्टी की अधिकतम नकदीकरण राशि पिछली सेवा में सेवानिवृत्ति के समय, जैसा भी मामला हो, और एक साथ ली गई छुट्टियाँ, तीन सौ दिन से अधिक नहीं बढ़ सकेगी।
- (5) उप-नियम (4) के अंतर्गत निर्वाचन आयुक्त आयोग में अपने कार्यालय छोड़े जाने की तारीख को लागू दर पर छुट्टी वेतन पर देय महंगाई भत्ता पाने के पात्र होंगे, इसके अलावा ऐसी छुट्टी के लिए वे कोई अन्य भत्ता पाने के पात्र नहीं होंगे।
- (6) निर्वाचन आयुक्त को एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी देय होंगी। निर्वाचन आयुक्त की आकस्मिक छुट्टी प्रशासक द्वारा स्वीकृत की जाएगी।
- (7) आकस्मिक छुट्टी को रविवार और अन्य अवकाशों के साथ मिलाया जा सकेगा और एक बार में ये छुट्टी 10 दिन से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए।
- (8) आयुक्त छुट्टी यात्रा रियायत के लिए उसी दर पर तथा उसी वेतनमान में तथा उन्हीं शर्तों पर पात्र होंगे, जैसा दिल्ली उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के मामले में लागू होती हैं।
- (9) निर्वाचन आयुक्त को छुट्टी प्रदान करने अथवा अस्वीकृत करने तथा उन्हें प्रदान की गई छुट्टियाँ बहाल करने अथवा उनमें कटौती करने की शक्ति प्रशासक को विहित होगी।
- (10) किराया मुक्त आवास, वाहन प्रभार सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रावधान संबंधी सेवा की शर्तें और सेवा की ऐसी अन्य शर्तें, जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 के अध्याय IV के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए लागू शर्तें और उक्त अधिनियम के तहत बने नियम निर्वाचन आयुक्त के लिए लागू होंगे।
- (11) निर्वाचन आयुक्त के लिए सेवा की ऐसी शर्तें जिनके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, इन नियमों और आदेशों के द्वारा निर्धारित की जाएगी जैसा भारत सरकार के सचिव स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए लागू हैं।
- (12) निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति, प्रति वर्ष चार हजार सात सौ सोलह रुपए की दर से पेंशन पाने का पात्र होगा बशर्ते, यदि उन्होंने आयोग में दो वर्ष से कम सेवा की होगी तो कोई पेंशन नहीं दी जाएगी।
- बशर्ते इस नियम के तहत निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य करते समय, देय औसत पेंशन राशि के साथ-साथ पेंशन के कम्प्यूट हुए हिस्से, यदि कोई हो, की राशि ली गई हो अथवा लिए जाने के पात्र हों, तो उक्त राशि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित पेंशन की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत कोई भी व्यक्ति सामान्य बीमा निधि (केंद्रीय सेवा) में अंशदान के लिए पात्र होगा।
8. इस अधिनियम में अन्यथा उल्लिखित के रूप में सुरक्षित करते हुए, यात्रा भत्ते, किराया-मुक्त आवास और आय कर से छूट प्राप्त राशि संबंधी सेवा की शर्तें, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 के अध्याय प्ट के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए लागू किराया-मुक्त आवास, वाहन भत्ता सुविधाएं, व्यय संबंधी भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं और सेवा की ऐसी अन्य शर्तें और उक्त अधिनियम के तहत बने नियम निर्वाचन आयुक्त के लिए लागू होंगे।
9. निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसके नुकसान के अनुसार सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

मनीषा सक्सेना, सचिव (शहरी विकास) निदेशक / (स्थानीय निकाय)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT**(Directorate of Local Bodies)****NOTIFICATION**

Delhi, the 13th November, 2019

No. F. 1(9)/ADLB/OS-5/2015/000372362/14143-53.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 7 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, and in supersession of the Election Commissioner of National Capital Territory of Delhi (Conditions of Service and Tenure of Office) Rules, 1993 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby make the Election Commissioner of National Capital Territory of Delhi (Conditions of Service and Tenure of Office) Rules, 2019 namely:-

Rules to determine the conditions of service and tenure of office of the Election Commissioner of National Capital Territory of Delhi for matters connected therewith or incidental thereto.

CHAPTER-I**PRELIMINARY**

- 1. Short title and commencement-** (i) these rules may be called the Election Commissioner of N.C.T. of Delhi (Conditions of Service and tenure of office) Rules, 2019.
(ii) These shall come into force at once.
- 2. Interpretation –** (1) In these rules unless the context otherwise requires:-
 - (a) 'Act' means the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) as amended till date.
 - (b) 'Administrator' means the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi.
 - (c) 'Election Commissioner' means the Election Commissioner appointed under section 7 (1) of the Act and under articles 243K and 243 ZA of the Constitution of India.
 - (d) 'Government' means the Government of National Capital Territory of Delhi.
 - (e) 'Judge' means a Judge of the High Court of Delhi.

CHAPTER II**SALARY AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE OF THE ELECTION COMMISSIONER**

- 3.** The Administrator may appoint an Election Commissioner from amongst the Indian Administrative Service Officers serving or have retired as Secretary to Government of India (U.T.s cadre) or as Chief Secretary/Principal Secretary working /retired as such in the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Apex scale of pay. The salary, allowances and other perquisites payable to and other conditions of service of the Election Commissioner shall be the same as admissible to a sitting judge of the High Court of Delhi as contained in the High Court Judges (Condition of services) Act, 1954 (No. 28 of 1954) and the rules made thereunder and instructions on this subject issued by the Government of India and the State Government from time to time.

Provided that if the Election Commissioner at the time of his appointment is in a receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service his salary in respect of service as the Election Commissioner shall be reduced –

- (a) by the amount of that pension; and
- (b) If he has, before such appointment received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service the commuted, value thereof by the amount of that portion of the pension.

Provided further that in no case the Election Commissioner shall be paid the salary less than what was admissible to him at the time of retirement prior to his appointment as Election Commissioner.

Provided further that the service conditions about which there is no provision under these rules, shall be the same as are, for the time being, applicable to the members of the Indian Administrative Service of the corresponding pay level in the Government.

TERM OF OFFICE

4. The Election Commissioner shall hold office for a term of six years from the date on which he assumes his office or attains the age of Sixty Five years whichever is earlier.

Provided that after the expiry of the aforesaid period the State Election Commissioner shall continue to hold the office until his successor is appointed and the successor assumes the office but this period in no case shall be more than six months.

Provided further that the Election Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Administrator, resign his office.

Provided further that the Election Commissioner shall not be removed from office except in a like manner and on the like grounds as a Judge of the High Court of Delhi.

5. (1) Any person who is appointed as the Election Commissioner may be granted leave in accordance with the provisions of sub-rule (3) of Rule 6 of these rules as hereunder prescribed.

(2) The power to grant or refuse leave to the Election Commissioner and to revoke or curtail leave granted to him shall vest in the Administrator.

6. (1) Where an Election Commissioner demits office (whether in any manner specified in rule (4) or by resignation), he shall, on such demission, be entitled to –

- (a) a pension which is equal to the pension payable to Judge of the High Court of Delhi
- (b) such pension including commutation of pension, family pension and gratuity as are admissible to a Judge of the High Court of Delhi
- (2) Except where the Election Commissioner demits office by resignation, he shall be deemed, for the purpose of these rules, to have demitted his office, if and only if
 - (a) He has completed the term of office specified in rule 4, or
 - (b) He has attained the age of sixty-five years, or
 - (c) He is removed from office in a like manner and on the like grounds as judge of the High Court of Delhi.
- (3) A person on appointment as Election Commissioner shall be entitled to the following leave namely –
 - (i) Earned leave of thirty days for every completed calendar year of service or a proportionate number of days for a part thereof and the leave salary for earned leave shall be equivalent to his salary drawn prior to proceeding on leave.
 - (ii) Half pay leave on medical certificate or on private affairs of twenty days in respect of each completed calendar year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave.
 - (iii) Leave on half pay can be computed to full pay leave if it is taken on self-Medical ground and is supported by a Medical Certificate from the competent medical authority.
 - (iv) Extraordinary leave without pay and allowances upto a maximum of one hundred eighty days in one term of office, however, there shall be no break in the term of office due to such leave if availed on the ground of self-illness.
- (4) On the expiry of a term in the Commission, the Election Commissioner shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of earned leave standing to his credit subject to condition that the maximum of leave encashed under this sub-rule or at the time of retirement from previous service as the case may be or taken together shall not in any case exceed Three Hundred days.
- (5) The Election Commissioner shall be entitled to receive dearness allowance as admissible on the leave salary under sub-rule (4) at the rates in force on the date of the relinquishment of their office in the Commission that he shall not be entitled to any other allowance on such leave.
- (6) Casual leave is admissible to the Election Commissioner upto 15 days in a calendar year. Casual leave for the Election Commissioner shall be sanctioned by the Administrator.

(7) Casual leave combined with Sunday and other authorized holidays should not exceed 10 days at a time.

(8) The Commissioner shall be entitled to leave travel concession at the same rate and at the same scale and on the same conditions as are applicable to a judge of the High Court of Delhi.

(9) The power to grant or refuse leave to the Election Commissioner and to revoke or curtail leave granted to him, shall vest with the Administrator.

(10) The conditions of service relating to provision for rent free accommodation, conveyance facilities, medical facilities and such other conditions of service as are for the time being applicable to a Judge of the High Court of Delhi under Chapter IV of the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 and the rules made thereunder shall so far as may apply to the Election Commissioner.

(11) The conditions of service of the Election Commissioner for which no express provisions are made in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to an Indian Administrative Service officer of the rank of Secretary to the Government of India.

(12) Person appointed as an Election Commissioner, shall be entitled to pension calculated at the rate of rupees four thousand seven hundred sixteen per annum provided that no such pension shall be payable, if he has put in less than two years of service with the Commission.

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office of the Election Commissioner shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a Judge of the High Court of Delhi.

7. Every person holding office as Election Commissioner shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund (Central Services).

8. Save as otherwise provided in this Act, the conditions of service relating to travelling allowances, rent-free accommodation and exemption from payment of income tax on the value of such rent free accommodation, conveyance facility, sumptuary allowances, medical facility and such other conditions of service, as are, for the time being, applicable to a Judge of High Court of Delhi under Chapter IV of the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 and the rules made thereunder, shall so far as may be, apply to the Election Commissioner.

9. The conditions of service of the Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANISHA SAXENA, Secy. (Urban Development)/Director (Local Bodies)